राजस्थान बजट 2026-27: एक विश्लेषण

Budget Analysis and Research Centre Trust
बजट अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र
(www.barctrust.org)

उप मुख्यमंत्री (वित्त) दिया कुमारी ने वर्तमान भाजपा सरकार का तीसरा बजट पेश करते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा । राज्य बजट में विकसित राजस्थान 2047 के विज़न को साकार करने के लिए पिछले बजट में लिए गए 10 संकल्पों, जिसमें बुनियादि ढांचा का विस्तार, बुनियादि नागरिक सुविधाएं पानी बिजली- सड़क, औद्योगिक विकास, मानव संसाधन का सशक्तिकारण, सुशासन एवं डिजिटल परिवर्तन, कृषि विकास एवं किसानों का कल्याण, हरित विकास, एवं पर्यटन, कला एवं सांस्कृतिक धरोहर आदि शामिल हैं, को दुहराया और उनके अनुसार ही बजट पेश किया।

राज्य आर्थिक स्थिति

बजट के साथ जारी किये गये आर्थिक समीक्षा 2025 -26 के अनुसार राज्य में स्थिर कीमतों पर अर्थव्यवस्था वृद्धि की दर एवं 2023-24, 2024-25, और 2025-26 में क्रमशः 7.66 प्रतिशत, 8 .77 प्रतिशत, और 8.66% रही है। अगर प्रचलित दरों पर अर्थव्ययस्था की वृद्धि की रफ्तार देखें तो या थोड़ी सुस्त हुई है । 2022-23 और 2023-24 में प्रचलित दरों पर राज्य की अर्थव्ययस्था जहां 12.8% की दर से बढ़ी वहीं यह 2024-25 में 11.77% और 2025-26 में 10.24% रह गई। आर्थिक समीक्षा के अनुसार, वर्ष 2025 - 26 में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय प्रचलित दरों पर 2.02 लाख रूपए है जो पिछले वर्ष से मात्र 9% अधिक है|

सारणी 1: सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में वृद्धि दर (प्रतिशत)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
स्थिर (2011-12) मूल्यों पर	5.45	-1.82	8.95	6.36	7.66	8.77	8.66
प्रचलित मूल्यों पर	9.71	1.79	17.46	12.8	12.85	11.77	10.24

स्रोत : राजस्थान आर्थिक समिक्षा 2025-26

कृषि, जिस पर राज्य की अधिकांश जनता निर्भर है, की वृद्धि दर घटकर वर्ष 2025 -26 में स्थिर मूल्यों पर लगभग शून्य रह गई, वहीं औद्योगिक वृद्धि की दर भी मात्र 7.56% प्रतिशत है। सेवा क्षेत्र में 2025-26 में आर्थिक वृद्धि की दर 11.15 प्रतिशत रही।

सारणी 2: स्थिर (2011 - 12) बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में वृद्धि की दर (%)

क्षेत्र	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य	5.71	-2.12	9.43	6.29	5.63	7.57	**7.03**
कृषि क्षेत्र	12.27	6.3	2.5	4.2	3.43	7.56	**0.22**
उदयोग क्षेत्र	4.43	2.68	9.31	4.42	7.68	5.87	**7.02**
सेवा क्षेत्र	2.78	-10.22	14.57	8.88	5.7	8.67	**11.15**

स्रोत : राजस्थान आर्थिक समिक्षा 2023-24

बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती

राज्य की आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार, राज्य में 2023-24 में बेरोजगारी की दर 4.7% जो देश भर में 3.5% की बेरोजगारी की दर से कहीं अधिक है। ऐसे में राज्य में कृषि और उद्योगों में धीमी आर्थिक वृद्धि चुनौतीपूर्ण है । राज्य की आधी (51%) कार्यशील आबादी कृषि में संलग्न है लेकिन 2025-26 में कृषि विकास स्थिर हो गई है और उद्योगिक वृद्धि भी सुस्त हुई है।

राजस्थान रोज़गार नीति 2026: राज्य सरकार ने इसी वर्ष, **राजस्थान रोज़गार नीति 2026** जारी किया है, जिसमें मार्च 2029 तक स्वरोज़गार, दैनिक मजदूरी और उद्यमशीलता पर ज़ोर देते हुए 15 लाख रोज़गार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है।

रोज़गार नीति 2026 में स्वयं सहायता समूहों, और लखपति दीदी, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, वन आधारित आजीविका, और 125 दिन की रोज़गार गारंटी; सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की बढ़ावा, कपड़ा, हस्तशिल्प, नवीकरणीय ऊर्जा, और कुशल कामगारों के लिए विदेशों में रोज़गार में सहायता; पर्यटन, होम स्टे, कार्यस्थल सुविधा (कोऑर्किंग स्पेस), और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तथा सरकारी नियुक्तियों में पारदर्शी, समयवध प्रक्रिया पर जोर दिया गया है।

वित्तीय स्थिति

इस वर्ष (2026-27) बजट का आकार 6.11 लाख करोड़ का है जो वर्तमान वर्ष (2025-26) के बजट अनुमान से 13.76 प्रतिशत तथा संशोधित अनुमान से 9.3 प्रतिशत अधिक है।

सरकार की राजस्व प्राप्तियां भी वर्तमान वर्ष के 2.94 लाख करोड़ रूपए (बजट अनुमान) से बढ़कर 2026-27 में 3.25 लाख करोड़ (बजट अनुमान) रूपए हो गई हैं। उसी प्रकार सरकार का राजस्व व्यय 3.25 लाख करोड़ रूपए (2025-26 बजट अनुमान) से बढ़कर 3.50 लाख करोड़ रूपए हो गया है। हालांकि राजस्व व्यय का एक बड़ा हिस्सा (लगभग 36 प्रतिशत) वेतन एवं पेंशन पर खर्च तथा 12.5% ब्याज पर व्यय होता है।

इस तरह सरकार का राजस्व घाटा 24,313 करोड़ रूपए रहने का अनुमान है, जो वर्तमान वर्ष से के राजस्व घाटा (बजट अनुमान) से लगभग 7 हजार करोड़ रुपये कम है । वहीं, 2026-27 में पूंजीगत व्यय 53,978 करोड़ रुपये होना अनुमानित है, जो वर्तमान वर्ष के बजट अनुमान के बराबर ही है। **परंतु वर्तमान वर्ष 2025-26 में पूंजीगत खर्च का संशोधित अनुमान बजट अनुमान से 26% कम रह गया है।** सरकार का **राजकोषीय घाटा,** जो लगभग उसी साल में लिये गये ऋण के बराबर होता है, 2026-27 में 79 हज़ार करोड़ रहने का अनुमान है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.69 प्रतिशत है।

विभिन्न क्षेत्रों (sectors) का बजट

नीचे परिशिष्ट सारणी 1 में अलग अलग मदों पर किए गए बजट आवंटन को दिखाया गया है। अलग-अलग क्षेत्रों की बात करें तो स्वास्थ्य में राजस्व बजट कुल राजस्व व्यय का 8 प्रतिशत है परन्तु स्वास्थ्य में कुल व्यय (राजस्व एवं पूंजीगत) कुल बजट का मात्र 5.5 प्रतिशत ही है । **स्वास्थ्य बजट में वर्तमान वर्ष (2025-26) के मुकाबले सिर्फ 2% की बढ़ोतरी हुई है । शिक्षा के बजट में वर्तमान वर्ष के बजट अनुमान से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।** लेकिन शिक्षा क्षेत्र में पूंजीगत खर्च में जरूर बढ़ोतरी हुई है। राज्य में विद्यालयों की जर्जर स्थिति को देखते हुए यह बढ़ोतरी बहुत ज़रूरी थी। लेकिन वहीं स्वस्थ्य का पूंजीगत बजट पहले से 16% तक कम हो गया है । पोषण के लिए भी 2026-27 के बजट में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है लेकिन पोषण का पूंजीगत बजट भी बढ़ा है। यहाँ ध्यान की बात यह है कि सामान्यतः स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण आदि सामाजिक सेवाओं में पूंजीगत खर्च पहले से ही काफी कम रही है । 2026-27 में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण का पूंजीगत बजट इनके कुल बजट का क्रमशः 15%, 6%, और 3% ही है।

2026-27 में कृषि एंव सम्बद्ध क्षेत्र, ग्रामीण विकास एवं शहरी विकास का बजट वर्तमान वर्ष (2025-26) से ठीक ठाक बढ़ा है। **हांलाकि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के बजट में कोई वृद्धि नहीं हुई है। जल एवं स्वच्छता के बजट में भी कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है।**

शिक्षा, युवा एवं रोजगार

जैसा कि चर्चा हुई इस वर्ष राज्य की रोज़गार नीति की घोषणा हुई है । साथ ही इस वर्ष एक राजस्थान युवा नीति 2026 भी जारी की गई। हालांकि पिछले वर्ष भी एक युवा नीति 2025 जारी हुई थी। ये दोनों ही नीति दस्तावेज़ राजस्थान यूथ बोर्ड के वेबसाईट पर मौजूद हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि इतनी जल्दी एक नई नीति लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी । राजस्थान युवा नीति 2026 का उद्देश्य है शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता और नेतृत्व विकास के द्वारा युवाओं के सशक्तिकारण और राज्य के समावेशी विकास। बजट में भी युवाओं के स्वयारोज़गार पर जोर दिया गया है और ये कहा गया कि युवा रोज़गार लेने वाला नहीं रोज़गार देने वाला बने। इसके लिए 'मुख्यमंत्रा युवा स्वरोजगार योजना' में एक लाख युवाओं को 10 लाख रुपये तक के ऋण पर शत-प्रतिशत ब्याज अनुदान तथा मार्जिन मनी अनुदान की घोषणा की गई तथा राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की घोषणा की गई है । साथ ही हर ज़िले में निजी क्षेत्र के साथ Institute of Skill Development and Vocational Training की स्थापना की घोषणा की गई।

लेकिन अगर रोज़गार गारंटी योजनाओं की बात करें तो ग्रामीण रोज़गार गारंटी के लिए VBGRAMG योजना के लिए 6750 करोड़ रुपये रखे गए हैं और मगनरेगा के लिए 699 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस प्रकार दोनों को मिलाकर ग्रामीण रोज़गार गारंटी के लिए कुल 7499 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं जो वर्तमान वर्ष से 1479

करोड़ रुपये अधिक हैं । परंतु क्या ये राशि सभी रोज़गार कहने वाले परिवारों को 125 दिन का रोज़गार उपलब्ध करवाने के लिए काफी होगी। शहरी रोज़गार गारंटी योजना के लिए इस वर्ष भी 200 करोड़ रुपये ही आवंटित हुए हैं जो पिछले 3 वर्षों से नहीं बढ़ा है (परिशिष्ट सारणी 2)।

स्कूल शिक्षा में, उन सभी विद्यालयों में जहां शौचालय नहीं हैं, शौचालय निर्माण और 2,500 विद्यालय भवनों के मरम्मत और जीर्णोद्धार हेतु 5500 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है।

मानसिक स्वस्थ्य को ध्यान में रखते हुए, 'सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य' के दीर्घकालिक लक्ष्य की प्राप्ति के RajMAMTA (Rajasthan Mental Awareness] Mentoring and Treatment for All) कार्यक्रम तथा सभी जिला मुख्यालयों पर Mental Health Care Cell की स्थापना की जाएगी । इसके साथ ही 'नशामुक्त राजस्थान' की संकल्पना को साकार करने के लिए Raj-SAVERA (Statewide Antidrugs Vigilance] Enforcement] Rehabilitation and Awareness) कार्यक्रम की भी घोषणा की गई ।

अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बजट

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति विकास निधि की राशि की घोषणा नहीं हुई इसलिये यह पता नहीं कि इन निधियों का आकार क्या होने वाला है। हालांकि अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण (अल्पसंख्यक सहित) मद के बजट में 500 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है और ये 2026-27 में ये लगभग 4 हजार करोड़ है ।

महिलाओं एवं बच्चों के लिए भी घोषणाएं की गईं। लखपति दीदियों को मिलने वाले कर्ज़ की सीमा 1 लाख से बढ़ कर 1.50 लाख रुपये, रुरल बीपीओ तथा राज सखी स्टोर की घोषणा, मुख्यमंत्रा नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत महिला/shg को दिये जाने वाले ऋण की सीमा 50 लाख (पचास लाख) रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया गया। किशोर बालिका योजना (Scheme for Adolescent Girls) को अब सभी 27 aspirational ब्लॉकक्स में लागू किया जाएगा। साथ ही राज्य में एक Rajasthan State Early Childhood Care] Development and Education Policy नीति लाने की घोषणा भी की गई । **लेकिन सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (जिसमें महिला एवं बाल विकास) तथा पोषण (समेकित बाल विकास योजना, किशोरी बालिका योजना, तथा मातृत्व लाभ योजना आदि) के बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।** सामाजिक सुरक्षा पेंशन का बजट भी 2025-26 के बजट अनुमान से समान ही है (परिशिष्ट सारणी 2)।

राज्य में जेन्डर बजट का का आकार जरूर कुछ (लगभग 11 हजार करोड़ रुपये) बढ़ा है। मुख्य रूप से यह बढ़ोतरी श्रेणी ब (ऐसी योजनाएं जिसमें 70% से कम महिला लाभार्थी होती हैं) में हुई है।

सारणी 3: राज्य में जेन्डर बजट (करोड़ रुपये एवं राज्य बजट का प्रतिशत)

	2024-25 ब अ	**2025-26 ब अ**	**2026-27 ब अ**
श्रेणी अ	11276.14	11494.46	12,319.53
श्रेणी ब	42739.21	51800.75	61,992.68
कुल	54015.35	63295.21	74,312.21
राज्य बजट का %	10.9	11.78	12.16

पर्यावरण संरक्षण एवं सतत् विकास पर ज़ोर

इस बजट में भी पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया है तथा पिछले वर्ष के बजट से आरंभ किए गए ग्रीन बजट में बढ़ोतरी की बात भी की गई है। बजट में हरियलो राजस्थान के तहत 10 करोड़ पेड़ लगाने, जिला स्तर पर नमो नर्सरी और पंचायत समिति स्तर पर नमो वन लगाए जाने की घोषणा, मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तृतीय चरण के तहत आगामी वर्ष लगभग 5 हजार गांवों में 2 हजार 500 करोड़ रुपये की लागत से जल संग्रहण के लिए निर्माण, अद्योगिक गंदे जल की सफाई के लिए बलोतरा एवं अन्य जगहों पर EFTP के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

साथ ही अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए इसकी करीब 4 हजार हेक्टेयर बंजर (degraded) भूमि के reclamation के लिए पक्की दीवार एवं जल संरचनाओं का निर्माण एवं स्थानीय प्रजातियों का बीजारोपण करवाने और खान, पुलिस एवं वन विभाग के समन्वित प्रयासों से अवैध खनन पर प्रभावी कार्यवाही किए जाने की घोषणा की गई।

हालांकि बंजर भूमि को पुनः खेती योग्य बनाने के लिए पक्की दीवार बनाने की योजना कितनी कारगर होगी यह प्रश्न भी उठता है। इस पूरी योजनां के पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन कर के ही इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए ।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 1: क्षेत्रवार बजट (करोड़ रूपए)

क्षेत्र		2023-24 ब अ	2023-24 वा	2024-25 ब अ	2024-25 वा	2025-26 ब अ	2025-26 सं अ	2026-27 ब अ	2025-26 सं अ में ब अ से वृद्धि (%)	2026-27 में 2025-26 के ब अ से वृद्धि (%)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	18,038.27	19,270.03	23,479.19	22435.1	**26228.44**	25508.16	27785.47	-2.75	5.94
	पूंजीगत	4,026.15	2,002.84	4,180.98	3242.91	**5659.6234**	4659.71	4740.84	-17.67	-16.23
	कुल	**22,064.42**	**21,272.87**	**27,660.18**	25678.01	31888.06	30167.87	32526.31	-5.39	2.00
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	राजस्व	56052.03	49,277.26	62,516.14	60723.87	**65780.54**	61655.07	65014.07	-6.27	-1.17
	पूंजीगत	1,900.87	**1942.48**	2,556.58	1135.78	**2588.32**	3604.52	3975.41	39.26	53.59
	कुल	**57,952.90**	**51,219.74**	**65,072.72**	61859.65	68368.86	65259.59	68989.48	-4.55	0.91

जल एवं स्वच्छता	राजस्व	4,488.27	4643.379	5,196.34	5376.314	6368.4167	6337.9685	6756.5017	-0.48	6.09
	पूंजीगत	5,284.99	3176.159	6,073.71	5154.24	7190.16	4300.42	7530.61	-40.19	4.73
	कुल	**9,773.26**	**7,819.54**	**11,270.05**	10530.56	13558.5772	10638.391	14287.115	-21.54	5.37
शहरी विकास	राजस्व	7,790.26	6842.943	10,629.90	7632.82	10550.22	10373.70	11130.53	-1.67	5.50
	पूंजीगत	6,249.82	2032.997	6,288.19	2229.58	6261.24	2395.32	9053.06	-61.74	44.59
	कुल	**14,040.08**	**8,875.94**	**16,918.09**	9862.40	16811.46	12769.02	20183.59	-24.05	20.06
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (महिला कल्याण सहित)	राजस्व	14485.42	13298.17	17433.26	14987.88	19229.37	16419.01	19281.29	-14.61	0.27
	पूंजीगत	80.87	125.26	145.42	90.58	119.01	35.91	106.87	-69.82	-10.20
	कुल	**14566.30**	**13423.44**	**17578.69**	**15078.47**	**19348.38**	**16454.93**	**19388.16**	-14.95	0.21
पोषण	राजस्व	3,046.61	2533.047	3,654.76	3263.82	3621.63	3588.86	3645.42	-0.90	0.66
	पूंजीगत	17.0007	34.6508	30.0344	2.1443	102.56	2.31	130.57	-97.74	27.30

	कुल	**3,063.61**	**2,567.70**	**3,684.79**	3265.96	3724.19	3591.17	3775.99	-3.57	1.39
अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण (अल्पसंख्यक सहित)	राजस्व	2,334.47	1509.585	2,676.71	2074.88	2772.80	2859.22	3373.89	3.12	21.68
	पूंजीगत	766.87	459.7991	829.6	434.56	809.06	888.33	705.62	9.80	-12.78
	कुल	**3,101.34**	**1,969.38**	**3,506.31**	2509.45	3581.86	3747.56	4079.51	4.63	13.89
उर्जा (बिजली+पेट्रोलियम+नवीकरणीय ऊर्जा)	राजस्व	23,512.80	**27040.44**	28,054.52	32574.19	36945.4283	33310.315	41190.234	-9.84	11.49
	पूंजीगत	1,610.76	**1854.32**	1,576.80	170	3253.0219	1062.5907	1562.138	-67.34	-51.98
	कुल	**25,123.56**	**28,894.76**	**29,631.33**	32744.19	40198.4502	34372.905	42752.372	-14.49	6.35
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	राजस्व	11,930.97	**10945.66**	13,742.26	10169.86	**15537.67**	15317.78	17395.151	-1.42	11.95
	पूंजीगत	932.65	**891.65**	802.22	515.7849	**1020.82**	1183.6008	816.8196	15.95	-19.98
	कुल	**12,863.62**	**11,837.31**	**14,544.48**	10685.65	16558.4914	16501.38	18211.97	-0.34	9.99
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	राजस्व	2,483.22	**2343.74**	2,871.49	2697.034	**3259.79**	3201.92	3621.9401	-1.78	11.11
	पूंजीगत	6,285.54	**5085.95**	6,934.67	5391.378	7766.8884	6629.4533	7587.7214	-14.64	-2.31

	कुल	**8,768.76**	**7,429.68**	**9,806.16**	8088.412	11026.6819	9831.3733	11209.662	-10.84	1.66
ग्रामीण विकास	राजस्व	19,418.30	**12014.14**	19,479.74	14167.37	23585.5516	24793.207	30502.107	5.12	29.33
	पूंजीगत	1,000.11	**842.18**	1,014.03	1000.035	1000.5	1707.82	2445.5	70.70	144.43
	कुल	**20,418.40**	**12,856.32**	**20,493.77**	15167.4	24586.0516	26501.027	32947.607	7.79	34.01

नोट: ब अ - बजट अनुमान, स अ - संशोधित अनुमान, वा- वास्तविक व्यय

स्रोत : राजस्थान बजट विभिन्न वर्ष

परिशिष्ट सारणी 2: मुख्य योजनाओं का बजट (करोड़ रूपए)

	2024-25 ब अ			**2024-25 सं अ**			**2024-25 वा**			**2025-26 ब अ**			**2025-26 सं अ**			**2026-27 ब अ**		
	राज्य	**केंद्र**	**कुल**	**राज्य**	**केंद्र**	**कुल**	**राज्य**	**केंद्र**	**कुल**	**राज्य**	**केंद्र**	**कुल**	**राज्य**	**केंद्र**	**कुल**	**राज्य**	**केंद्र**	**कुल**
वृद्धजन पेंशन	8625	385.45	**9010.45**	8021	632.97	**8653.97**	7990.05	229.6053	**8219.655**	10411	256.47	**10667.47**	8772.6	532.75	**9305.35**	10411	256.47	**10667.47**
विधवा पेंशन	3450	211.88	**3661.88**	3237.1	333.23	**3570.33**	3225.225	158.2037	**3383.428**	4184	153.47	**4337.47**	3443.5	341.31	**3784.81**	4184	153.47	**4337.47**
विएशेष योग्य	1019	13.31	**1032.31**	920.3	21.36	**941.66**	918.3116	9.2273	**927.5389**	1187.4	8.96	**1196.36**	872.5	13.02	**885.52**	1187.4	8.96	**1196.36**

जन पेंशन																		
शहरी रोज़गार गारंटी	300	0	300	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
मनरेगा	1616.463	3402	5018.463	1335.032	3402	4737.032	592.9941	2007.497	2600.491	1636.03	4384.5	6020.53	1680.373	4140.171	5820.545	699.04	0.00	699.04
VBGRAMG																2753.12	3996.88	6750